

Shrimati Lakshmi Menon: It has already been stated in the answer that the Central P.W.D. will look after the road for the next two years.

Shri Shree Narayan Das: May I know whether the expenditure incurred for the maintenance and repair of this road will be borne by the Government of India or by the Government of Nepal?

Shrimati Lakshmi Menon: It is a part of the Government of India's responsibility under the Colombo Plan to construct this road and maintain it for two years.

श्री गंगानगर जिले में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

+

* १७६१. { श्री पहाड़िया :
श्री प० ला० बाक्याल :

क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री गंगानगर जिले के भूमिहीन हरिजन और गैर-हरिजन विस्थापित व्यक्तियों को खेती के लिये जमीन देकर बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ,

(ख) क्या सरकार को विदित है कि श्री गंगानगर में अनेक विस्थापित व्यक्ति बिना किसी सरकारी सहायता के पड़े हुये हैं ; और

(ग) यदि हा, तो क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर खन्व खन्ना) : जिला गंगानगर में दोनों, दावेदार और गैर दावेदार शरणार्थियों को, जिन में हरिजन भी शामिल हैं, निकासी कृषि जमीनें दी गई हैं ।

(ख) और (ग) मन १९५५ के अधिनियम में लोक सभा के एक सदस्य ने मंत्रालय को एक सूची भेजी थी जिन में उन व्यक्तियों

के नाम थे जिन्हें कोई जमीन नहीं दी गई । पड़ताल करने पर यह सूची अधूरी पाई गई, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन, दावेदार, गैर-दावेदार और पता आदि जैसी जरूरी बातों की तफसील नहीं दी गयी थी । हमें मालूम हुआ है कि जांच कराने के लिये राज्य सरकार अधूरी तफसीलों को पूरा करने के लिये माननीय सदस्य के साथ पत्र व्यवहार कर रहा है ।

श्री पहाड़िया : मैं जानना चाहता हूँ कि गंगानगर जिले में अब तक ऐसे कितने भूमिहीन हरिजन और गैर-हरिजन शरणार्थी हैं जिन्हें जमीन दे दी गई है और कितनों को अभी तक नहीं दी गई है ?

श्री मेहर खन्व खन्ना : हमने गंगानगर में इस वक्त तक १७,६७७ फेमिलीज को जमीन दी है और उसमें कितने हरिजन हैं और कितने गैर-हरिजन, यह हम नहीं जानते क्योंकि हमने रिहेबिलिटेशन के मामले में हरिजनों और गैर-हरिजनों में कोई सास तमीज नहीं की है :

श्री प० ला० बाक्याल : जो अधूरी सूची भेजे दी है, उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ और एक पूरी सूची भेजने की तैयार हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि उनको बसाने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रबन्ध किया जाएगा ?

श्री मे र खन्व खन्ना : आज इस वक्त तो इसका जवाब देना मुश्किल है । १७,००० के करीब परिवारों को जिला गंगानगर में बसाया जा चुका है और जो क्लेमेट्स हैं उनको देन के लिए भी हमारे पास जमीन नहीं है । ऐसी सूरत में गैर-क्लेमेट्स की तो बारी भेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से ही आने वाली है ।

Sardar Iqbal Singh: May I know whether the Government has any figures of the evacuee land which is in the possession of local persons in Rajasthan?

Shri Mehr Chand Khanna: I have not got the figures at the moment, but it is a fact that a big area of evacuee land is in the possession of local persons in Rajasthan.

Sardar Iqbal Singh: May I know whether any steps have been taken to take back that area and given it to the displaced persons?

Shri Mehr Chand Khanna: I have been in correspondence with the State Government for the last two years or so. I have not met with any success so far.

Shri B. K. Gaikwad: What is the number of Harijan refugees and non-Harijan refugees? May I know how the land has been distributed among them; what land has been allotted to Harijan refugees and what land has been allotted to non-Harijan refugees?

Shri Mehr Chand Khanna: My Ministry deals only with displaced persons, and we make no distinction between Harijans and non-Harijans

श्री पी० ला० बाबूपाल : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में क्या हम यह मान कर चलें कि जो १०,००० के करीब वहाँ शरणार्थी पड़े हुए हैं, सरकार की धीर से उनको कोई सहायता नहीं मिलेगी ?

श्री मेजर चन्द्र खन्ना : जनाब, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ।

O. phangunj Market, Calcutta

*1791-A. **Shri Biren Roy:** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state—

(a) the total amount of taxes and rates, if any, paid by the Government of India to the Corporation of Calcutta in the shape of taxes for conservancy and water supply of Orphananj Market at Calcutta during the last three years;

(b) whether there have been representations by the Shopkeepers' Associa-

tion against the administration of this Market; and

(c) if so, the nature of the representations and steps that Government have taken or intend to take to remedy the state of affairs?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): (a) The total amount of taxes paid by the Government of India to the Corporation of Calcutta in the shape of taxes for conservancy and water supply for the last three years, viz., 1954-55, 1955-56 and 1956-57, are Rs. 7104, Rs. 7704, and Rs. 8130 respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) The allegations related to both insanitary conditions and mal-administration. The charge regarding mal-administration was not proved. To meet the criticism regarding insanitary conditions, such additions alterations and repairs as were considered essential were carried out.

Shri Biren Roy: Is it a fact that the shopkeepers and big wholesalers who are in that area, whenever they apply for partnership business to take new partners, experience delay and these are not disposed of even within six months or one year by the administrator in that area?

Shri Anil K. Chanda: I have no information.

Shri Biren Roy: Is it a fact that when the West Bengal Government are willing to take over the administration of this market when it is transferred, and in view of the reply given on the 24th August in this House that the matter is being gone into and it will shortly be transferred, would the hon. Minister see that the transfer is effected very soon?

Shri Anil K. Chanda: It is not a question of transfer. It is a question of sale, because the property belongs to the Government of India. We are in the final stages of negotiation with